

pressed by the Congress Members standing up.

श्री मधु लिमये : सदन की खुशी का सवाल ही नहीं है। यह नियम के विपरीत है। वह पैस ही नहीं हुआ है।

MR. SPEAKER: He had moved it.

So, it is withdrawn by leave of the House.

The motion was, by leave, withdrawn

11.43 hrs.

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 and to provide for certain related matters.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 and to provide for certain related matters".

The motion was adopted

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I introduce† the Bill.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 3rd September, 1973.

†Introduced with the recommendation of the President.

11.44 hrs.

Re. FLOODS IN SOME STATES

अध्यक्ष महोदय : कुछ संसदों गुजरात के फ्लड्स के बारे में कल-परसों मेरे पास कुछ मोशन ले कर आये थे। मैंने उनको एडमिट नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों की इजाजत से गुजरात के तीन चार मेम्बरों को दो दो, तीन तीन मिनट इस बारे में कहने के लिए देना चाहता हूँ। मैं राजस्थान के मेम्बरों को भी मौका दे दूंगा। जो मेम्बर मेरे पास आये थे, मैंने उनको इजाजत दी है। लेकिन इसकेशन के लिए टाइम नहीं है।

श्री बलंत साठे (अकोला) . मैंने भी रूल 377 के मानदण्ड नोटिस दिया है कि एल०आई०मी० ने कई हजार स्क्वियर फीट जमीन ट्रेडिंग को प्रॉक्टिकली फ्री दे दी है। मुझे भी इजाजत दी जाये।

श्री मधु लिमये (बाबा) . अध्यक्ष महोदय, मैंने बाकायदा नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई मोशन नहीं आ सकेगा। जिन मठभ्या ने कहा है कि उनको दो दो, तीन तीन मिनट का मौका दिया जाये मैं उनका इजाजत दे दूंगा।

SHRI P. M MEHTA (Bhavnagar) : With your permission, I would make a submission on the Narmada floods....

अध्यक्ष महोदय . इस के लिए टाइम फिक्स कर दिया जायेगा। तब आप अपनी बात कह लें।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : . उम के बारे में मिनिस्टर साहब ने कहा है....

श्री मधु लिमये : आप मंत्री महोदय का जवाब पढ़िये। वह श्लतबदानी कर रहे हैं।

MR. SPEAKER: I will ask Minister when he comes back to read the statement himself.

श्री मधु लिमये : पहले मुझे प्रश्न करने कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : जब वह आयेंगे।

Immediately after the passage of the Code of Criminal Procedure Bill, I will allow one hour for brief speeches for two or three minutes by members who are affected by the recent floods in Gujarat and Rajasthan to impress upon the Government the need for appropriate action.

श्री हुसैन चन्द कच्छवाय (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सदस्यों को भी मौका दिया जाये।

श्रीमती सहोदराबाई [राय (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भी बाढ़ आई है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल पास होने के बाद आप भी कह लीजिएगा।

11.48 hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
BILL.—contd.

CLAUSES—contd.

MR. SPEAKER: Further clause by clause consideration of the Bill to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure, as passed by Rajya Sabha.

This Bill must be disposed of within two hours. That is the commitment in this House. The House was devoting the whole of its time Saturday to this.

New Clause 485A

SHRI MADHU LIMAYE (Banks):
I beg to move.

Page 148, after line 4,—insert—

"485A. (1) When any person under the age of fifteen years is sentenced by any Criminal Court to imprisonment for any offence, the Court may direct that such person, instead of being imprisoned in a criminal jail, shall be confined in any reformatory established by the State Government as a fit place for confinement, in which there are means of suitable discipline and of training in some branch of useful industry or which is kept by a person willing to obey such rules as the State Government prescribes with regard to the discipline and training of persons confined therein.

(2) All persons confined under this section shall be subject to the rules so prescribed.

(3) This section shall not apply to any place in which the Reformatory Schools Act 1897, is for the time being in force". (261)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन कोई नया संशोधन नहीं है। जो वर्तमान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उस की धारा को मंत्री महोदय ने नये बिल में काटने का निर्णय किया है। इस का कारण क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। वर्तमान कोड की धारा में वह प्रावधान है कि यदि पंद्रह साल, या उस से कम उम्र के लड़कों की सजा हो जाती है, तो उन को जेल में रखने के बजाये रेफ्रेमेटरी में भेज दिया जाये। अब इस धारा को काट देने के बाद मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या उन को आप जेलों में भेज देंगे? जेलों में जो बस उम्र के लड़के होते हैं उन के साथ बड़ी ज़्यादती होती है। मंत्री महोदय जानते हैं, श्री स्वराज्य के पहले के जमाने में जो बाल बच्चों में यह